आजादी के साठ साल और हमला खुदरा बाजार पर

–मीनाक्षी अरोरा

आजादी मिले साठ वर्ष पूरे हो रहे हैं। लम्बे संघर्ष और कितने ही लोगों की बलिदान के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को गोरे भारत छोड़कर जाने पर मजबूर हुए थे। बलिदानियों की आंखों में भारत के बारे में अपने सपने थे। संप्रभु, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, सद्भावना और सबको रोजी–रोटी की सुरक्षा जैसे अनगिनत सपने देखे थे शहीदों ने। पर आज के नए किस्म के कंपनीराज– बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद के दौर में, भारत ने पहली बार घुटने टेके विश्वबैंक ओर मुद्राकोष के दबाव में, जब केन्द्र सरकार ने नयी आर्थिक नीति–1991 घोषित की। यह नीति और कुछ नहीं, विश्वबैंक और मुद्राकोष का ढाँचागत समायोजन कार्यक्रम था, जिसमें भूमण्डलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, विनियमितीकरण, मुक्त बाजार एवं व्यापार, सबसिडी में कटौती आदि की वे नीतियां शामिल थीं जिन्हें इन ब्रैटनवुड्स संस्थाओं ने भारत सरकार को लागू करने की शर्त पर कर्ज देते समय लगायी थी। दूसरी बार भारत ने आत्मसमर्पण किया 15 अप्रैल 1994 को जब उसने डब्लूटीओ (विश्वव्यापार संगठन) का मसविदा स्वीकार करके उसकी सदस्यता ले ली। मसविदा (मोरक्को) में हुई सन्धि प्लासी की संधि का अन्तरराष्ट्रीय संस्करण था। इसमें भारत ने कानूनी रूप से स्वीकार कर लिया कि वह अपने नियम, कानून, प्रशासनिक व्यवस्थाएँ डब्लूटीओ के आदेशानुसार बनायेगा। 'हमारे देश में इतिहास को महिमामंडन की बीमारी बहुत पुरानी है–साथ ही एक कड़वी सच्चाई यह है कि वर्तमान की गुलामी किसी को दिखती नहीं है।' भारत के तत्कालीन वाणिज्यमंत्री प्रणव मुखर्जी देश के गले में नयी गुलामी का फंदा डलवा कर मर्राकेश से लौटे। मर्राकेश में डब्लूटीओ सन्धि पर हस्ताक्षर होते ही उत्तर की विजय हो गयी। उस वक्त गैट के महानिदेशक पीटर सदरलैंड ने कहा था कि यह आधुनिक आर्थिक और राजनैतिक इतिहास में नया मोड़ देने वाला क्षण है।

अब दुनिया की अर्थव्यवस्था और व्यापार पर इस नयी तिकड़ी–विश्वबैंक, मुद्राकोष और डब्लूटीओ का शिकंजा कस गया है। ये तीनों संस्थाएं अमरीका, यूरोपीय संघ ओर जापान के कब्जे में हैं। वे दुनिया के देशों को अपनी मर्जी से नचाती हैं। भारत में इस तिकड़ी ने उद्योग, वित्त, सेवा और कृषि क्षेत्र को विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए खुलवा लिया है। अब एक बड़ा क्षेत्र बचा है खुदरा व्यापार का।

बहुराष्ट्रीय परचूनिया आ रहे हैं !

अब आजादी के 60वें साल में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारे देश का खुदरा व्यापार या परचूनी के धंधा पर कब्जा करने की अनुमति दी जा रहा है। फुटकर विक्रेताओं को कारोबार से बेदखल करने की मुहिम तेज हो गई है। परचून के क्षेत्र में उतरने के लिए विश्वव्यापी खिलाड़ी कमर कसे तैयार खड़े हैं। देश के बड़े औद्योगिक व्यापारिक समूहों ने पहले ही भांप लिया था कि फुटकर कारोबार सबसे बड़ा उदीयमान क्षेत्र है। इसलिए चालू सहस्राब्दि के दस्तक देते ही उन्होंने उगते हुए एक नए सूरज को सलाम ठोंका है और अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर नए–नए लुभावने तौर–तरीके अपनाते हुए धूमधड़ाके के साथ वे इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। इसके साथ उन्हें यह भी लालच है कि अगर बहुराष्ट्रीय व्यापारिक निगमों के उतरने के पूर्व वे खुदरा व्यापार के क्षेत्र में अपनी पहचान, बढ़त या उपस्थिति कायम कर लेते हैं, तो फिर ये विश्वव्यापी कारोबारी उनकी इकाइयों के साथ गठजोड़ या भागीदारी करेंगे ही और इस तरह दुनिया भर में ये भी मैदान मार लेंगे। भले ही आगे चल कर वे अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के नाममात्र के जूनियर पार्टनर या दुमछल्ले भर बन कर रह जांय और यह भी हो सकता है कि बहुराष्ट्रीय परचूनिया उन देशी खिलाड़ियों का सफाया कर दें, जिनकी बांह पकड़कर कभी ये इस देश में दाखिल हुए थे। इसके साथ–साथ शुरू हो जाएगा, देश के

करोड़ों खुदरा विक्रेताओं की बेकारी तबाही और आखिरकार आत्महत्या का सिलसिला, जो किसानों में जारी है अब परचूनियों को अपने लपेटे में ले रही है। यह कैसी आजादी है?

परम्परागत खुदरा व्यापार

आज तो घर–घर की यह कहानी है कि अगर कोई नौजवान बेरोजगार है और हर जगह वह हाथ–पांव चला चुका है, फिर भी उसे रोजगार नहीं मिला है, तो वह थोड़ी सी पूंजी अपने मित्रों, परिजनों, परिचितों, सगे संबंधियों आदि से जुटा कर फुटकर सामानों की अपनी दुकान खड़ी कर लेता है। यह भी आम बात है कि उसे अपने धंधे के लिए बहुत सारा सामान उधारी या साख पर मिलता रहता है। बिक्री करते रहने पर जो नकदी उसे मिला करती है, उससे वह थोक व्यापारी या उत्पादक को भुगतान करता जाता है, फिर वह नया माल लेता है और इस तरह उसकी रोजी–रोटी चलती रहती है। ऐसे लोगों की तादाद हमारे यहां करोड़ों में है।

ऐसे परिवारों की संख्या हमारे यहां बेशुमार है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुदरा व्यापार से अपना गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। देश में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर खुदरा बिक्री करके जीवन यापन करने वाले लोग न हों। देश के कोने–कोने में फैले खुदरा कारोबार के सुविस्तृत क्षेत्र पर बहुराष्ट्रीय परचूनियों की नजर बहुत दिनों से लगी हुई थी। उनके भाग्य से छींका तब टूटा, जब भारत सरकार के आला मंत्रियों के नीति निर्धारक समूह ने उन्हें इस क्षेत्र में उतरने की हरी झंडी दे दी। परम्परागत परचून के दिन अब लदने वाले हैं, उसका स्थान लेने जा रहा है, संगठित किराना व्यवसाय। इसके व्यापक 'फारमेट' के साथ बहुराष्ट्रीय किराना खरीददारी देशी खिलाड़ियों को मोहरा बना कर बरास्ता फ्रँचाइजी भारत में बाकायदा सेंधमारी कर चुके हैं। बहरहाल अब तो पलक पांवड़े बिछा कर उनके स्वागत की तैयारियां जोर–शोर से चल रही हैं। देश के बड़े संगठित किराना कारोबारी उनके लिए जमीन तैयार कर चुके हैं। उनके मुक्त प्रवेश के रास्ते में जो रही सही अड़चनें थीं, सरकार उन्हें भी दूर करने जा रही है। मकड़जाल का तानाबाना तैयार हो रहा है। हजारों विशाल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पेटे में मेमने जैसे भारतीय परचूनिए समाने को अभिशप्त हैं। नए जयचंद और मीरजाफरों की फौज उनका स्वागत करने को तैयार हैं।

खुदरा व्यापार बनाम कारपोरेट किराना व्यवसाय श्रृंखला

यह कहा जा रहा है कि देश के फुटकर दुकानदारों को चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। देशी औद्योगिक या कारोबारी समूहों द्वारा अपने अभिक्रम से या विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की फ्रेंचाइजी विशेष विक्रय अनुज्ञा लेकर खोली गई संगठित किराना व्यवसाय श्रृंखलाओं के पैरोकार यह कहते नहीं थकते कि वे श्रृंखलाएं और खुदरा दुकानें दोनों साथ–साथ बिक्री कर सकती हैं क्योंकि दोनों के सहअस्तित्व से वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में काफी बढ़त होगी और फिर दोनों के पास अलग–अलग किस्म के खरीददार आते हैं। इसलिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी परचून व्यवसाय पूरी तरह खोला जाना चाहिए। लेकिन विकसित देशों के अनुभव कुछ और ही बताते हैं। इंगलैण्ड के संगठित फूड रिटेलिंग बिजनेस के बारे में 'मिशेल/ए.सी. नियलान' ने एक अध्ययन किया था, जिसके निष्कर्ष अगस्त 2000 में छपे थे। उस अध्ययन के मुताबिक संगठित फूड रिटेलिंग बिजनेस में वर्ष 1981 के दौरान 56,862 स्वतंत्र परचूनिया थे, 1993 में इनकी संख्या 32,600 तथा 1999 में इनकी संख्या 25,800 पर आ गई। इस प्रकार 1993–1999 की अवधि में इनकी संख्या में कुल 21 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

खुदरा व्यापार में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शामिल होने का दुष्परिणाम यह होगा कि देश में बनने वाली चीजों को बिक्री के लिए वे अपनी दुकानों में नहीं रखेंगी, जिसके चलते यहां के उद्यम चौपट होंगे। वे बाहर से सामान मंगाएंगी और उन्हें इस देश के उपभोक्ताओं के गले तरह–तरह के हथकंडे

अपना कर मढ़ेंगी। आउटसोर्सिंग करना उनका पुराना आजमाया हुआ नुस्खा है। जिसकी कीमत इस देश को अपने अधिसंख्य लोगों की रोजी–रोटी की बलि देकर चुकानी होगी।

मीरजाफर और जयचंद जैसे लोग तो इस देश में हमेशा से रहे हैं लेकिन यहां के जनगण के पास असहयोग, बहिष्कार और आखिरकार होलिकादहन के अपने अनूभूत अचूक और सिद्ध प्रयोग भी हैं। लड़ाई जारी है ....खुदरा पर बहुराष्ट्रीय कब्जे से रोकने के लिए 9 अगस्त को राजधानी की सड़कों पर उतरेंगे हजारों लोग। नवधान्य की डॉ वंदना शिवा, कनफेडेरेशन ऑव आल इंडिया ट्रेडर्स, एकोर्न–इंडिया एफडीआई वॉच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, राष्ट्रीय व्यापार मंडल, लोकराज संगठन, भारतीय मजदूर संघ, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया कॉआर्डिनेशन कमेटी ऑव ट्रेड यूनियन्स, पवनपुत्र रेहड़ी–पटरी खोमचा संघ, बाम्बे ट्रेडर्स फेडरेशन, एनएपीएम, नेशनल हॉकर्स फेडरेशन सहित देश के कई संगठनों के लोग 9 अगस्त से 15 अगस्त को 'खुदरा मुक्ति अभियान' के रूप में मनाएंगे।

संगठनों ने अपील की है कि ''अब समय आ गया है, जब समाज के सभी वर्गों को परचूनी कारोबार में कंपनियों के हमले के खतरों को समझना है और इन राक्षसों से लड़ने के लिए एकजुट होना है। यह फेरीवालों, व्यापारियों, किसानों, उपभोक्ताओं, ट्रांसपोर्ट लाइन के लोगों यानी समाज के सभी वर्गों के लिए खतरनाक है। कंपनियों की चालबाजियों से सावधान हो जाइए! वे कभी किसी समाज का भला नहीं करतीं। उन्हें हर कीमत पर केवल और केवल अपना मुनाफा चाहिए। पश्चिम की तरह कहीं हमारे देश को भी इनके द्वारा किये गए विनाश की कीमत न चुकानी पड़े।

वालमार्ट, रिलायंस और टेस्को जैसे बड़े खुदरा व्यापारी रोजगार, समाज, पर्यावरण के विनाश के एजेंट हैं। किसानों और गलियों के बाजारों को बचाने और सुपर मार्केट की एकाधिकारी प्रवशत्ति का विरोध करने के लिए विश्वव्यापी आंदोलन हो रहे हैं। जिस विविधता और विकेन्द्रीकरण की पश्चिम को तलाश है। वह भारत में पहले से मौजूद है, हमें अपनी ऐसी लघु–खुदरा व्यवस्था को बचाना है। आइए अपने परम्परागत परचूनी कारोबार पर हमले के खिलाफ आंदोलन में जुट जाएं और उन करोड़ों लोगों का साथ दें, जो इससे अपनी रोजी चलाते हैं। अपनी जीविका, अपने लोग, अपना देश बचाइए।''(पीएनएन)

आलेख प्रकाशित होने की स्थिति में कतरन और पारिश्रमिक राशि 'पीपुल्स न्यूज नेटवर्क' के नाम भेजें
संपादक मंडल– अमित सेनगुप्ता, अरूण अग्रवाल, भारत डोगरा, ई पी मेनन, हर्ष डोभाल, जावेद नकवी, प्रशांत भूषण, संजय काक
पीपुल्स न्यूज नेटवर्क (समाचार विचार सर्विस)
पीएनएन 14 सुप्रीम एंक्लेव, मयूर विहार फेज 1, दिल्ली–91, Email- pnnhindi@gmail.com